also depend on thern to discharge it as best as they could.

DR. K. MATHEW KURIAN : Please allow me to make one interruption. The suggestion by Mr. Niren Ghosh was not for this particular incident only. An all-Party parliamentry committee could look into the whole question of running of the coalmines on the nationalised pattern in view of the fact that coal is the most precious material today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): That question he has already dealt with.

SHRI T. A. PAI: This is quite a different suggestion. I would certainly like to be advised by any Member, in any part of the House. 1 am sure most of tbem who have been connected with the coal industry in one capacity or the other might be able to advise me much more intimately but whether a committee should be constituted for this purpose I shall certainly take it into consideration and come to a decision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Next business. Shri Nawal Kishore

MOTION RE: TWENTIETH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR THE YEAR 1970-71—contd.

SHRl NAWAL KISHORE (Uttar Pradesh) : Shri Mirdha wants to say something.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Yes. Mr. Mirdha.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Madam, Shri Kumbhare during his speech mentioned about the action-taken statement on this Report. So, with your permission, I would like to inform him and the" other Members of this House that five copies of the action taken statement on the Twentieth Report have been placed in the Parliament Library.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि आज हिन्दुस्तान की आजादी के 26 साल के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में इस हाउस को, इस सदन को वाद-विवाद करने की जरूरत पड़ आई है। हम यह समझते थे कि देश की आजादी के बाद, जब हमारा संविधान बना, देश इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि छुआछूत और ऊंच नीच का जो भाव हमारे समाज में है, जो सदियों से कोढ़ की तरह हमारे समाज को ग्रसित करता रहा है, यह खत्म हो जाएगा, जो आर्थिक विषमताएं हैं, वे भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी, मगर आज 26 साल के बाद यद्यपि यह सही है इस बीच में काफी काम हुए हैं, यह मैं नहीं कहता, नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में जिस हद तक सुधार हम चाहते थे उस हद तक सुधार नहीं हुआ है। मिर्धा साहब जब अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने प्रि-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेन्टर्स बनाए हैं, यह अच्छी बात है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। यह भी उन्होंने बताया कि आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० और जो सेन्ट्रल क्लास वन् सर्विसेज हैं उनमें करीब-करीब जो शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राईब्स का जो कोटा है रिजर्वेशन का, संरक्षण का वह पूरा हो चुका है। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं मिर्धा साहब से—क्लास वन् की बात ठीक है—मगर यह जो क्लास 3 और क्लास 4 जिसको कहते हैं, जो ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर के एम्प्लाइज हैं, उनके बारे में स्थिति क्या है? क्योंकि 26 साल से, एक जमाने से मांग आती थी, पहले से भी इस बात की मांग थी—और मैं समझता हूं, इसमें तथ्य भी था; क्योंकि हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत अनुभव है—कि जो हायर सर्विसेज थीं, उनके बारे में कहा

[श्री नवल किशोर]

जाता था कि उनके अन्दर अच्छे कैन्डिडेट्स नहीं मिलते, लेकिन जो छोटी सर्विसेज हैं। जैसे कि आपके रेलवेज में एम्प्लाइज होते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर में होते हैं, जहां कोई ख़ास स्पेशल योग्यताएं या क्वालिफिकेशन्स की आवश्यकता नहीं होती है, वहां उनका कोटा पूरा क्यों नहीं होता? क्यों यह चीज एक जमाने से चली आती है, हालांकि मैं आपको यह बताऊं कि करीब-करीब 9 करोड़ से ज्यादा की तादाद हमारे देश में हरिजनों की, शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स की है, इस तरह से उनमें 2—4 हजार आदमियों को आप एब्जार्ब कर भी दें, तो भी मैं नहीं समझता उससे उनकी जनरल आर्थिक स्थिति सम्भल जाएगी। मैं नहीं जानता मिर्धा साहब का क्या विचार है, लेकिन मुझे तो यह भी लगता है यह जो रिजर्वेशन है यह एक स्पून-फीडिंग है। मैं नहीं जानता मेरे दोस्तों के ख़यालात क्या हैं, लेकिन फिर भी आन् द पौइन्ट आफ नाट बीइन्ग मिस्-अन्डरस्टुड, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी यह फीलिंग है कि यह जो आपका कांटिन्युएशन है—रिजर्वेशन आप रखिए—मैं इसके अगेन्स्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें उनमें कोई स्वावलम्बन की भावना तेजी से पैदा हो, मुझे इसके अंदर भी शक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह आपका रिजर्वेशन भी आहिस्ता-आहिस्ता व्हेस्टेड इन्टरेस्ट बनता जाता है। मिर्धा साहब को मैं याद दिलाऊं कि जिस समय मैंने निगाह डाली दो-चार दफा, अपने स्टेट में भी और अपने स्टेट के बाहर भी, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कुछ पहले जमाने में आगे आ गईं, जैसे कुछ एक फैमिलीज या तो एम०पीज हैं या एम० एल० एज हैं, दूसरे वह कि जो लड़के आई० ए० एस० में आ गए, उनके बारे में क्या मिर्धा साहब मेरे दोस्तों की राय जान कर यह कोशिश करेंगे कि आई० ए० एस० में आने के बाद कम से कम उस आदमी को डि-शेड्यूल्ड कर दिया जाए, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जब एक आदमी टॉप के ऊपर आ गया तब भी पुरानी श्रेणी में रह जाए। मुझे कभी-कभी अजीब सी बात लगती है कि एक गरीब ब्राह्मण का बेटा फीस नहीं मांग सकता, लेकिन एक सेन्टर के मिनिस्टर के बेटे की फीस माफ होगी। क्यों माफ होगी? तो मैंने केवल संकेत मात्र यह बात कही कि कम से कम जो लोग समाज के ऊपर उठ कर आ जाएं, जो क्लास एक या दो की सर्विस में आ जाएं, उनको कम से कम आहिस्ता-आहिस्ता डि-शेड्यूल्ड कर दीजिये ताकि वे भी समाज में इंटिग्रेट हो सकें। हालांकि मैं यह बात मानता हूं कि इसमें आपको दिक्कत पड़ेगी, लेकिन मैंने इशारा कर दिया है।

आपने बजीफे की बात कही कि हम 70 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रुपया इसमें लगाना चाहते हैं, तो यह एक अच्छी बात है। जो छोटा तबका है अगर उसको आगे बढ़ाते हैं तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड क्लास है उसको भी हमें हर तरह की सहायता करनी चाहिये, क्योंकि बैकवर्ड कोई किसी जाति से नहीं होता है। मेरा तो कहना यह है कि हमारे समाज में जो गरीब तबका है, उनको भी बजीफा दिया जाना चाहिये ताकि वे भी समाज में अपने को ऊंचा उठा सकें।

आपने बताया कि ट्राइबल्स के लिए ब्लाक बनाये जायेंगे। यह बात ठीक है और मैं इस बात की डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। एक बात आप देखिये और वह आपकी किताब में भी है। प्लानिंग कमीशन ने यह माना है कि 44 प्रतिशत आबादी हिन्दुस्तान की ऐसी है जो अपना जीवन नीचे स्तर पर काट रही है। क्या आपने पता लगाया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे आते हैं? मेरा तो अपना यह ख्याल है कि मेजारिटी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों की होगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस तरह के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं?

हमारे देश म 1 करोड़ 27 हजार आर्गनाइज्ड लेबर है और इनकी तादाद इतनी है कि वे

ट्रेन बन्द कर सकते हैं, कारखाने बन्द कर सकते हैं और अस्पताल बन्द कर सकते हैं। आप इन लोगों की तनख्वाह तो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, मगर जो भूमिहीन किसान हैं, जो भूमिहीन मजदूर है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनकी कोई संगठित यूनियन नहीं है, न कोई आर्गनाइजेशन ही है, उनको मिनिमम वेजेज देने के बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, न उनकी वेज फिक्स की है और जो कुछ भी उनके लिए किया गया है, उसको आप अच्छी तरह से इम्पलीमेंट नहीं कर पाये हैं।

श्री मिर्धा साहब एक योग्य व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त है, लेकिन उनकी याद-दिहानी के लिए में फिर उनका ध्यान खींचना चाहता हूं।

SHRI N. H. KUMBHARE:To refresh their memory.

SHRI NAWAL KISHORE: Article 3S says :

"The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

मैं मिर्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने विधान में इस तरह की व्यवस्था की है कि जिनकी उम्र 21 वर्ष की है वे वोट दे सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। मैं उन क्षेत्रों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई कम्युनिटीज ऐसी हैं, जिनका मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता हूं; क्योंकि मिर्धा साहब भी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर हरिजनों को आजादी के साथ वोट डालने नहीं देते हैं। वहां पर हरिजनों को आतंकित किया जाता है, जिससे कि वे अपने वोट का प्रयोग न कर सकें। उन लोगों को इस तरह से पोलिटिकल अधिकार होते हुए भी उस अधिकार को इस्तेमाल करने का कोई साधन नहीं है और न ही आपने अभी तक इस तरह के लोगों के लिए कोई व्यवस्था की है। आर्थिक स्थिति भी उन लोगों की अभी तक वैसी ही है जैसे कि पहिले थी और उन्हें अभी तक गन्दगी के कामों को करने से छुटकारा नहीं मिला है।

इसके बाद मैं आर्टिकल 39 (ए) में आता हूं।

"That the citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood."'

सेक्शन 32, 34 और 35 में जहां पर मिनिमम नैसेसिटीज की बात कही है उसको आपने 1975 तक बढ़ा दिया है। पहिले ही से इन लोगों के लिए मिनिमम नैसेसिटीज की व्यवस्था थी और अब आपने 10 साल और बढ़ा दिया है।

अब आप 'ई' में देखें —

"That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age."

'एफ' में यह कहा गया है—

"That childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

आप घरों में देखते हैं कि जो घरेलू नौकर हैं, वे छोटी उम्र के होते है। 12-14 साल के होते हैं और वे ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही होते हैं, मगर इन लोगों के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। आपने सरकस में जो लेडीज काम करती हैं, उनको मैटर्निटी बैनीफिट तो दे दिया है। इस बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है और यह आपने एक अच्छा काम किया है। लेकिन मैं यह कहना

चाहता हूं कि जो औरतें खेतों में काम करती हैं, उनके लिए आपने मैटर्निटी बैनीफिट के लिए क्या व्यवस्था की है ? आज हमें स्वतंत्र हुए 26 साल हो गये हैं और मैं इस बात की ओर मिर्धा जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

"41. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education ana to public assistance in cases of unemployment, old age sickness and disablement, and in other cases of undeserved want "

आपने ओल्ड एज पेंशन तो कर दी है । हर स्टेट के अन्दर है या नहीं, यू० पी० के अन्दर तो है 75 साल से ऊपर वालों के लिए । आपने एजूकेशन की बात कही है । कम्पलसरी एजूकेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स के लिए भी नहीं है, औरों की बात तो छोड़ दें । 42 में कहा गया है ।

"42. The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief."

'ह्यूमैन कन्डीशन्स' में किस तरह काम किया जा रहा है। मैंने इन आर्टिकल्स को इसलिए कोट किया चूंकि इनका बहुत बड़ा वास्ता है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स से; क्योंकि वे वीकर सेक्शन हैं। आर्टिकल 46 और 47 पढ़ने के बाद मैं दूसरी बातें कहूंगा।

"46. The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and. in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

47. The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are. injurious to health."

मिर्धा साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, शायद आप भी नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता, लेकिन महाराष्ट्र में जहां गांधी जी पैदा हुए थे—उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक था—हमने प्राहिबिशन को खत्म कर दिया, 21 साल के हर बालिग को यह हक है कि उसको शराब पीने का परमिट मिल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से—कुम्बारे साहब मुझे माफ करेंगे—यह शौक आज हर आदमी में बढ़ गया है और इसका सबसे ज्यादा असर उन छोटे भाइयों पर पड़ता है जिनकी आमदनी कम है, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई काफी शामिल हैं। कुछ दिनों के बाद तो शायद गांधी जी का नाम लेना भी प्रतिक्रियावाद का एक सबूत हो जाएगा इस देश के अन्दर। खादी तो आपने खत्म कर दी। मिर्धा साहब, आप तो खादी पहनते हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर खादी पहनने वाले नहीं हैं सेन्ट्रल केबिनेट में। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपकी वर्किंग कमेटी में एक प्रपोजल आया था—पता नहीं प्राइम मिनिस्टर ने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया—जिसमें यह था कि खादी खत्म कर दी जाय और शराब पीने की छूट दे दी जाय। मैंने कहा बढ़िया, गांधी जी की सच्ची प्रतिनिधि कांग्रेस अब बनने वाली है । यह हालत हो गई है।

अब देखिए 'एट्रासिटीज आन हरिजन्स" । आप गुजरात को लें, आन्ध्र को लें, बिहार को लें, आप यू० पी० को लें—यू० पी० बांदा जिला तो इस काम के लिए मशहूर हो गया है—आप हरियाणा को लें, हर जगह से शिकायत आती है कि हरिजन भाइयों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है । इसके माने यह हैं कि बावजूद हमारी और आपकी कोशिश के समाज में वह इन्टीग्रेशन और वह भावना उन कमजोर व्यक्तियों के प्रति हम पैदा नहीं कर सके, जो करनी चाहिए थी । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सब काम गवर्नमेंट ही करेगी, मगर जनमत अभी तक तैयार नहीं हो पाया और उसकी जिम्मेदारी आपके प्रति भी बहुत हद तक है ।

अब आप लैंड सीलिंग की बात। आपने कानून बनाया, अच्छा कानून बनाया। हमने भी कानून बनाया उत्तर प्रदेश में जब 40 एकड़ की सीलिंग कर दी थी, मगर आपको ताज्जुब होगा कि 40 एकड़ की सीलिंग के बाद भी शायद ही कोई गांव ऐसा होगा, जिसमें किसी हरिजन को जमीन मिली होगी, वरना प्रधान जी के भाई भतीजों के नाम ही जमीन बंट गई। अब आपने सीलिंग 18 और 27 एकड़ कर दी। मिर्धा साहब, आपके पास इतना बड़ा पुलिस का महकमा है, अपने जमाने में इतना तो कर जाइए कि कम से कम गवर्नमेंट की पोलिसी के मुताबिक जो सरप्लस जमीनें हैं उनको हरिजन भाइयों को दिलवा दें। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपकी आज्ञा से, मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लेता, मैं भी गया था बुलन्दशहर, चाहे न हमारी पार्टी के हों या आपकी पार्टी के हों, जितने होशियार मिनिस्टर, एम० पी० और एम० एल० ए० थे उन सबने अपनी जमीनों के बेनामी ट्रांजेक्शन कर दिए। आप जाइए बुलन्दशहर के अन्दर जो बड़े-बड़े जमींदार थे, जिन्होंने कांग्रेस की आजादी की जंग को बुरी तरह पिटवाया था वे आज बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और आपकी नीतियों का पालन नहीं करते हैं। तो आप यह जमीन कहां से देंगे ? मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई कुम्भारे जी को, उन्होंने एक बात कही कि वह चाहते हैं कि प्रमोशंस में लोगों को हताश न होना पड़े। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे योग्य व्यक्तियों को प्रमोशन दिलाना चाहते हैं। अयोग्य व्यक्तियों की वह हिमायत नहीं करते हैं। मैं उनकी ताईद करता हूं और उन्हीं के शब्दों को दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि प्रमोशन मैरिट और सीनियोरिटी दोनों चीजों को कंबाइन करके होना चाहिए। वहां भी आपने गड़बड़ की तो वहां भी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी।

उन्होंने एक मांग की कि जुडिशियल अथारिटी बनाई जाए इंडिविजुअल ग्रिवांसेज को दूर करने के लिए, उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए कि उसमें काफी दिक्कतें होंगी। लेकिन इतनी बात सही है कि तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो इंडिविजुल ज्यादतियों को देखे और उनको दूर करने के लिए काम करे।

यह बात सही है कि अनटचेबिलिटी के बारे में लोगों में कुछ कांसियसनैस पैदा हुई है। लेकिन आज भी आप इंटीरियर में जाइये, गांवों में जाइये वहां शेड्यूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के आदमी—मैं नहीं जानता मिर्धा साहब अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी व्याधियां हैं जहां—आज भी चौधरी साहबान के साथ हरिजन भाई कुर्सी पर बैठ नहीं सकता है, बैठेगा तो उसे अपनी चांद मजबूत करनी पड़ेगी। मैं आपकी भी दिक्कत जानता हूं, आप चाहें कि कानून से इसे दूर कर दें तो वह भी नहीं कर पायेंगे। आज शहरों में तो थोड़ी जागृति इस बारे में हुई है, किन्तु बैकवर्ड एरियाज में, इंटीरियर गांवों में जागृति नहीं हुई है।

मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि आज 26 साल के बाद भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं, जहां लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता और खास तौर से आज भी हरिजन भाइयों की बहुत कम हिम्मत है कि वह गांव के हर कुएं से पानी भर सकें। 26 साल के बाद भी हम उन्हें पानी नहीं पिला सके।

मेरे भाई ने इंटर-कास्ट शादी की बात कही। आइडिया मिर्धा साहब बहुत अच्छा है, आइडिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं उसको बड़ा एप्रिशियेट करता हूं, मगर समाज की जो स्थिति है वह इंटर कास्ट मैरिजेज समाज में बाई फोर्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि और भी कम्युनिटिज में बाई फोर्स नहीं हो पाती। मिर्धा साहब मैं एक बात आप से कहूं कि अनटचेबिलिटी अमंग दि अनटचेबल्स आज है। मैंने गांव में एक बार यह कोशिश की कि बाल्मीकी भाइयों से सबको चाय पिलवा दूं, लेकिन 80 परसेंट जाटव भाई वहां से खिसक गये। तो यह अनटचेबिलिटी केवल हाइ-कास्ट्स में ही नहीं है, बल्कि लोवर कास्ट्स में भी है।

श्री मान सिंह वर्मा : आपने जो अंतर्जातीय विवाह की बात कही, उसको मैंने बाई फोर्स नहीं कहा है। मैंने कहा कि उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

श्री नवल किशोर : मैंने आपकी बात को एक्सेप्ट किया है।

[श्री नवल किशोर]

महोदया, तीन बातें कह कर खत्म करता हूं। बैंक से कर्जे की जो बात है वह बहुत अच्छी है। मिर्धा साहब, मैं आपसे बड़े काम की बात कह रहा हूं। आपके लोन सीक्योर हों या अनसीक्योर हों, जब तक आप अनसीक्योर लोन्स सीकर सेक्शन्स को नहीं देंगे, तब तक उनकी उन्नति होने वाली नहीं है। हमारे इन भाइयों में तो इनिशियेटिव कम होता है, एंटरप्राइज कम होता है। मैंने अपनी स्टेट में देखा कि कई हरिजन एस्टेट बनें, इन्डस्ट्रीज बनें, लेकिन वहां काम हो नहीं पाया लोगों में प्रोत्साहन देने के लिए आप लोन दें यह मुनासिब चीज है।

मकान की बात एक बहुत बड़ी बात है। आज गांवों में, शहरों में, गन्दी बस्तियों में यह बहुत बड़ी प्राबलम है। मैं मेहता साहब से, जो यहां बैठे हुए हैं, सेंट्रल के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, घर देने वाले आदमी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आपने इतनी कालोनियां बनाई हैं—इन्द्रपुरी, रामपुरी, सीता पुरी, इस तरह की कालोनियां बनाई है, आप एक कालोनी हरिजनों के लिए भी बनायें।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : नवल पुरी भी बना देंगे।

श्री नवल किशोर : आप उसका नाम हरिजन कालोनी रख दें तो मैं आपका मशकूर हूंगा।

आखिरी बात कह कर खत्म करता हूं। एक चीज है कि जो अफसरान हमारे हों उनको आस्था होनी चाहिए, हमारी स्कीम्स के अन्दर।

श्री नवल किशोर : यह मेरा बड़ा कटु अनुभव है। चाहे खादी की बात लीजिये, उसमें भी यही बात है। शाह साहब, आप गुजरात के रहने वाले हैं। आप मेरी बात सुनिये।

श्री चुनाई शाह (गुजरात) : मैं सुन रहा हूं।

श्री नवल किशोर : जिन को आप खादी का काम देते हैं उनको उसमें रुचि नहीं होती है। आप जिन को हरिजन कल्याण समाज अधिकारी बनाते हैं, वे खुद छुआछूत के शिकार होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को अगर आप को रेस्पेक्टिबिलिटी देनी है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इनको रिजर्वेशन भी दीजिये, आगे बढ़ाइये, मगर जब तक जनरल लेविल पर ये ऊंचे नहीं उठेंगे तब तक सौ दो सौ आदमियों को क्लास टू और क्लास वन कैडर को सर्विसेज देने से इनका कल्याण होने वाला नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के हर वर्ग में जागृति पैदा हो और ये समाज का जैसे एक अटूट अंग हैं वैसे ही इनका इंटिग्रेशन हो जाये, अमलगामेशन हो जाये और वह तब होगा जब यह छुआछूत, धर्म कर्म कम हो जाये।

इन शब्दों के साथ मैं मिर्धा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं, लेकिन उनमें और तेजी लाने की कोशिश की जाये। उनकी जो जेनुइन मांगें हैं, वे पूरी की जायें बशर्ते कि एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को बनाये रखा जा सके।

श्री बलराम दास (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि आज कमिश्नर की रिपोर्ट पर हम लोग विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमने जो गरीबी हटाने का संकल्प लिया है, उसी संकल्प के अन्दर यह एक कार्यक्रम है शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे बढ़ाने का। कमिश्नर की रिपोर्ट मेरे खयाल से इस बात की रिपोर्ट है कि गरीबी हम कितनी हटा सके हैं और अभी गरीबी कितनी बाकी है। वास्तव में यदि देखा जाये तो जैसा कि अभी नवल किशोर जी ने कहा कि हमारे देश में जितने बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा हरिजन और आदिवासी लोग आते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि हरिजन आदिवासियों के बारे में हमें जल्दी से जल्दी उन के उत्थान के लिए जो कुछ करना चाहिये, वह हम करें। लेकिन जो हमारे सामने कमिश्नर की रिपोर्ट

है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि जो गरीब हरिजन आदिवासी हैं, उनके बारे में आप देखिये कि सरकार उनको वजीफा कितना देती है । उस वजीफे के सहारे वे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तो पास करा लेते हैं, लेकिन जहां तक कालेज एजूकेशन का सवाल है, पोस्ट मैट्रिक एजूकेशन उन के वश का नहीं होता है । विद्यार्थी की यह तबियत होती है कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन उस के सामने गरीबी का सवाल होता है । मैंने होम मिनिस्ट्री को गत वर्ष कई पत्र लिखे कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का रेट बढ़ा दिया जाये, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने कई बार मुझे यही जवाब दिया है कि इस वक्त आर्थिक कठिनाई होने के कारण हम स्कालरशिप का रेट बढ़ाने में असमर्थ हैं । इस के साथ-साथ यह भी लिखा कि आप का जो सुझाव है यह गवर्नमेंट के अंडर कंसीडरेशन है । तो मैं मिर्धा साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्वयं सोचें कि जो हरिजन आदिवासी ग्रेजूएट या पोस्ट ग्रेजूएट स्टूडन्ट को 40, 50 रुपये महीने स्कालरशिप मिलता है उस में वह अपनी स्टूडेंट लाइफ कैसे लीड कर सकता है । चालीस पचास रुपया तो खाने के लिये भी नहीं होता है । जिस समय के यह पुराने रेट्स चले आ रहे हैं । उस समय से यदि हम हिसाब लगायें तो आज रुपये की कीमत आठ आने से भी नीचे चली गयी है । आज उस की कीमत 47 नया पैसा रह गयी है । तो आप सोचिये कि जिस विद्यार्थी को चालीस या पचास रुपये मिलते होंगे, आज उस स्कालरशिप की रकम की कीमत केवल बीस या पच्चीस रुपया ही रह गयी है । यह दुःख की बात है । मैं आप को एक सूचना देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हायर सेकेन्ड्री क्लास तक दस रुपया हर होस्टिलियर स्टूडेंट के लिये बढ़ा दिया है महंगाई को मद्देनजर रखते हुए । लेकिन जो स्टूडट कालेज में पढ़ते हैं उनकी आज बड़ी बुरी हालत है । किसी प्रकार उन के खाने के लिये हो जाता है तो कपड़े के लिये नहीं हो पाता और कपड़े के लिये हो जाता है तो उन को खाने के लिये नहीं हो पाता। कभी किता नहीं हो पाती और कभी कपड़ा, तो अन्त में इस सब का नतीजा यह होता है कि वह मेंटल फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन में अपनी स्टूडेंट लाइफ लीड करते हैं और उनमें से कुछ तो फेल हो जाते हैं और कुछ मुश्किल से थर्ड डिवीजन पास हो कर निकलते हैं और ऐसे स्टूडेंट जब सरकार के सामने किसी नौकरी के लिये जाते हैं तो वे बेचारे कंपीटीशन को पास नहीं कर पाते, इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते और इस प्रकार बेचारे दर-दर भटकते हैं । सामाजिक स्थिति हमारे यहां कुछ ऐसी है कि यदि वे किसी प्रकार का नया धंधा शुरू करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते, इसलिये कि उनके पास पूंजी नहीं होती । इस के अलावा मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि जो बी०ए० या एम० ए० पास हैं और अगर वह चाहते हैं कि वे चाय या पान की दुकान लगायें तो छूआ-छूत की वजह से वे चाय या पान की दुकान भी नहीं लगा पाते और इसलिये उनके पास सिवाय सरकारी नौकरी के अलावा और कोई जरिया नहीं होता । जिसके सहारे वे अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकें । इसलिये मिर्धा साहब से मेरा निवेदन है कि वे पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के रेट्स जरूर बढ़ायें । यदि वे उनके रेट्स नहीं बढ़ायेंगे तो उन विद्यार्थियों से जो उम्मीद की जाती है, उन से जो पोजीशन और डिवीजन लाने की उम्मीद की जाती है यह पूरी नहीं हो, सकती और उन का विद्यार्थी जीवन भी सुचारु रूप से नहीं चल पाता है ।

इसके अलावा मैं गांव के लोगों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अभी नवल किशोर जी ने एग्रीकल्चर लेबर के बारे में कहा । वास्तव में एग्रीकल्चर लेबर में यदि आप देखेंगे तो अस्सी या नब्बे प्रतिशत हरिजन और आदिवासी होते हैं। और उनकी यह हालत होती है कि दो रुपये और तीन रुपये रोज की मजदूरी पर उन को मजबूरन किसी जमींदार या किसी बड़े जागीरदार या भूमि-दार के अंडर रह कर मजदूरी या नौकरी करनी पड़ती है । सरकार ने मिनिमन वेजेज ऐक्ट पास किया है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता और

[श्री बलराम दास]

यदि कहीं होता भी है तो आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि जो उस में शेड्यूल दिया हुआ है वह प्रैक्टिकल नहीं है। वह आज आउट आफ डेट हो गया है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट को रिवाइज किया जाय और रिवाइज करके यह देखा जाय कि वास्तव में उस का इंप्लीमेंटेशन कितना होना चाहिये। वह हो रहा है या नहीं।

मैंने यह देखा है कि एक गांव में चमारों ने यह तय किया कि हम आज से मरे जानवर उठाने का काम नहीं करेंगे। यह उन्होंने तय किया। इसका नतीजा यह हुआ है कि दूसरे दिन से जब वे लोग सुबह काम पर गए तो उन को सब लोगों ने यह जवाब दिया कि भाई तुम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम मरे जानवर नहीं उठाएंगे और हम लोगों ने यह फैसला किया है कि अब हम चमारों से काम नहीं कराएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज वे इतनी मजबूरी में गांवों में रह रहे हैं, इतनी गुलामी में उनका जीवन बीत रहा है कि वे अपने जीवन सुधार के लिए, अपने सामाजिक सुधार के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए यदि वे कोई छोटा सा कदम भी उठाना चाहते हैं, तो गांव के लोग उनको हतोत्साहित करते हैं। उनके साथ अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। उनके रास्ते बंद करते हैं और नाना प्रकार से उनको सताया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मिनिमम वेज ऐक्ट को रिवाइज किया जाए और उसमें जो रेटस हैं, उसके रेट्स वगैरा अब बढ़ाने की जरूरत है।

लैंड सीलिंग के बारे में हर जगह चर्चा चलती है कि जो सरप्लस लैंड होगी वह हरिजन आदिवासियों को दी जाएगी। लेकिन मेरे खयाल से जो सरप्लस लैंड है उसका ऐक्ट बनते-बनते उसका इतना इल्लीगल ट्रांसफर अभी हुआ है जैसा अभी नवल किशोर जी ने भी कहा कि पहले जो लैंड सीलिंग हुई थी उसका इम्पलीमेन्टेशन मुश्किल हो गया था। यही हालत आज हमें नजर आती है। हमने जो लैंड सीलिंग बिल बनाया है उनका इम्पलीमेन्टेशन होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ यदि सरकार यह सोचे कि हम को इसका इम्पलीमेन्टेशन कराना है और जो भूमिहीन गरीब हरिजन आदिवासी हैं उनको हम भूमि जरूर दिलायेंगे और ऐसा निश्चय करके जो सरकारी मशीनरी है, वह सरकारी मशीनरी यह तय करे कि हम इनको पट्टे देंगे, इस जमीन को लीज पर देंगे तो लीज पर देने के साथ-साथ इसका जो कब्जा है, वह कब्जा भी देंगे। यह निश्चय करने की जरूरत है।

तहसीलदार और पटवारी क्या करते है ? तहसील में बैठ कर वह हरिजन आदिवासियों को पट्टा तो दे देते हैं, लेकिन वह यह नहीं देखते कि इस जमीन का कब्जा उस गरीब हरिजन आदिवासी को मिला है या नहीं। जब तक उनको कब्जा नहीं मिलता तब तक मैं समझता हूं कि हमारा जो लैंड अलाटमेंट प्रोग्राम है वह सफल नहीं होगा और जिस तरह पहले हुआ है वही अब भी होगा।

इसके साथ-साथ इस प्रोग्राम में पुलिस की मदद की भी जरूरत है। जैसे उसने जमीन को जोता, बोया, फसल तैयार की, लेकिन जब फसल पक कर खड़ी हो गई तो हमें यह देखने को मिलता है कि गांवों में उसकी खड़ी फसल को दूसरे लोग जबर्दस्त अपनी लाठी, डंडे और बन्दूक की ताकत से उस जमीन की फसल को काट लेते है और वह बेचारा हरिजन आदिवासी ऐसे ही रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। जब वह पुलिस में रिपोर्ट करने के लिये जाता है तो पुलिस ऐक्शन लेने की बजाय उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखती। मैंने तो यह देखा है कि पुलिस स्टेशन पर जो कांस्टेबल वगैरा होता है वह उस हरिजन आदिवासी से कहता है कि पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें पांच रुपये वाली रिपोर्ट लिखवानी है या 10 रुपये वाली लिखवानी है। तुम्हें 50 रुपये वाली रिपोर्ट लिखवानी है या 100 रुपये वाली लिखवानी है। उसके पास जब उस समय पैसा नहीं होता तो वह अपनी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकता है। यह स्थिति है। इसलिये मेरा शासन से, मिश्रा जी से और

दीक्षित जी से यह निवेदन है कि जब तक उनको पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दिया जायेगा, तब तक वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र भी हो जायें, तब भी वह सुरक्षित नहीं रह सकते । इसलिये मेरा शासन से यह निवेदन है कि जो भूमिहीन हैं उनको जमीन देने के साथ-साथ यह भी एक फालो-अप प्रोग्राम के रूप में देखना चाहिये कि आया वे उस जमीन के ऊपर खेती-बारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या उनको किसी प्रकार की परेशानी है या नहीं है । इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि तभी इसका सही मायनों में इम्पलीमेंटेशन होगा ।

इसके अलावा एट्रासिटीज के बारे में आज हिन्दुस्तान भर में चर्चा है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, लेकिन इसमें सब से बड़ी चीज यह है कि पुलिस की जितनी मदद उनको मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही है । जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ कि मध्य प्रदेश में अभी डाकुओं ने सरेन्डर किया, उनका दिल बदला, हृदय परिवर्तन हुआ, उसी तरह जो स्वर्ण वर्ग है उसके हृदय परिवर्तन की जरूरत है । जैसा कि डाकुओं के बारे में सोचा जाता था, यह मान्यता थी कि ये समाज के शोषक हैं, ये समाज के लोगों को परेशान करते हैं, ज्यादती करते हैं, उसी तरह स्वर्ण वर्ग के बारे में है जो कि गरीब हरिजन आदिवासियों को परेशान करते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन भी उन डाकुओं की तरह हो और उनको भी समाज में लोग डाकू मानें, यह माने कि यह गरीबों को सताने वाले डाकू हैं, इनसे हम लोग नफरत करें और उन लोगों को उसी प्रकार से सजा दी जाय जिस प्रकार कि डाकुओं को दी जाती है लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग ऐसे लोगों की और हिमायत करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं । यह हमारे समाज के लिये बड़े शर्म की बात है ।

(*Time bell rings*)

महोदया, घंटी बज गई है, अब मैं एक प्वाइंट और कहूंगा । सफाई कामगारों के बारे में, जो म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन में संडास की सफाई का काम करते हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हू । हमारा आजादी के 26 वर्ष पूरे हो चुके, लेकिन हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि आज भी हमारी गरीब बहनें और भाई अपने सिर के ऊपर मल-मूत्र की टोकरी और बाल्टी लेकर सड़कों से गुजरती हैं और मजबूरन उन्हें यह काम अपना पेट पालने के लिये करना पड़ता है । तो शासन से मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि मलकानी कमेटी ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी कि यह मल-मूत्र की जो ढुलाई सिर के ऊपर हमारी बहनें या भाई करते हैं, यह बन्द होनी चाहिये । उनकी सिफारिशों को हम जितनी जल्दी से जल्दी अमल में ला सकें वह उपयुक्त होगा और हमारे लिये एक बड़ी शान की और एक बहुत बड़ी बात होगी ।

इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAV): Dr. Z. A. Ahmad. Not here. Yes, Shri Sanat Kumar Raha.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal),: Madam Vice-Chairman, now we are discussing the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is the Twentieth Report. But the tragedy in our life is this that this Report which we are discussing now is not known to the Harijans at large. The Harijans do not know what the Constitution means for them, whether there is any Directive Principle for them or whether this Report will be to their benefit. 4 P.M.

SHRI B. T. IKEMPARAJ (Tamil Nadu): On a point of order. Mr. Raha should amend his statement that the Harijans do not know what the Constitution contains for them . . .

{Interruptions)

SHRI SANAT KUMAR RAHA: Harijans do not know this. The majority of them do not know what is there for them

[Shri B. T. Kamparaj]

in the Constitution. It is quite clear (hat the Harijans and the Scheduled Castes and the untouchable do not know whether the Constitution has given them some rights or not. We are discussing an exercise in futile. Year after year we are getting reports. Year after year, so many people in the august House are talking about the Harijans and untouchables. But the problem remains as it is. Our hon. friend, Mr. Man Singh Varma, said that this is not a question of politics. Sir, in my knowledge, in my experience, in my life, I know that on the one hand they are taken as have-nots, on the other they arc taken as sub-human—as sub-human race in the world. We have got one-fifth of sub-human population, that is, 13 crores. Even after 26 years of independence, these things are not known to the Harijans. What does this Report say ? I would like to quote from the Report.. I have gone through all the details of the Report, page by page. Every report says some very good things. But it is a matter of implementation. Is there any scheduled time for implementation? No. Can you give any promise ? They want democracj'. They want socialism. These are all slogans. Out of this political philosophy come ths removal of untouchability, removal of illiteracy, removal of vested interests—all these are connected together. So, politically, economically, socially and sociologically, I think, there must be one philosophy. There should be a society, there should be a system, which should be free from exploitation of man by man. This is my philosophy.

They, Sir, I came to some questions relating to the Reports which have been made for the implementation by the Government.

The Report has made a general review. The Report says that lack of sense of urgency is there. This will, political will, must come from the Government—this determined will to eradicate untouchability, to eradicate this blot, this stigma on our society, on our nation, which keeps 13 crores of our population as sub-human, neglected slaves and bonded labour.

Sir, I quote from the Report, Chapter I—'A General Review':

"Now that we are at the threshold of the Silver Jublee Year of our Independence, it is high time that we looked at the balance sheet of our socio-economic achievements and find out if we had been able, as envisaged in our Constitution, to guarantee individually as well as collectively, fruits of democracy to all citizens of India, particularly to those belonging to Weaker sections of the society—the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who have, for long, been socially suppressed and economically exploited ..."

This is how it starts. Is this indicative of the determination of the Government ? ls the Government determined to that extent ? There is doubt. I must say that within 10 years the Government should be determined and do its utmost to eradicate untouchability from the society. There is no magic wand which can remove untouchability. We are carrying forward centuries' old legacy and tradition. It was introduced by the vested ruling party at that time.

Again, this review says that the State shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people and particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from all social injustice and exploitation. This is the directive principle. You should send your party men to the villages and we shall send our party men to propagate this ideal of the Directive Principle of the Constitution. After 26 years of Independence, we are keeping mum. We have no imagination to uplift the Harijans. The first part of the report says that we must have determination and will to start an agitation. The Harijans must fight for their rights as a class. It should not be a gift, or bonus or charity or dole.

Then 1 come to page 19 of the report, quote, "The Supreme Court judgment makes it amply clear that the intention of the Constitution makers was to make adequate safeguards for the advancement of the backward classes and to secure for them adequate representation at all stages. ! If this safeguard is to be implemented in full, there should be no hesitation on the J part of the Government to go forward whole-heartedly and not half-heartedly with insufficient measures." I, therefore, reiterate that the principles of reservation must be accepted in all sincerity and that it should extended to cover cases of promotion to Class II and Class 1 posts also. What Supreme Court says; "We have every apprehension, every doubt, that the Government machinery is not functioning to the satisfaction of these directive principles." This is rather a structure from the Supreme Court.

I request that these recommendation of the Commissioner should be implemented by a tirne-bound programme. I would request the Minister to make a determined effort so that the implementation is achieved within a particular time. The implementation can be realised if there is determination. If there is no determination, there will be no implementation.

Then, there is a recommendation at page 14 about hostel facilities. Fifty per cent money should come from the Government and another fifty per cent from the voluntary organisations. I do not know whether this can be implemented, in order to provide all the facilities in each State in order to bring them at par with the urban students. Sir, I have already stated about the principle of reservation. The Government machinery should be alert regarding these reservations. Then, take the cases of de-reservation by the Planning Commission. The Department of Personnel issues orders to comply with the orders for reservations. There was a dispute between the Personnel Department and the Planning Commission. Ultimately, it has gone to the Commission. The Commission says that whichever circular has been issued by the Government should be implemented. And the Planning Commission sometimes recommended de-reservation. That sort of thing should not happen again.

Sir, this very Government is bringing out every year a good report for the upliftment of Harijans and tribal people. What is their performance ? The Scheduled Castes represent only 2.7 per cent in the case of Class I Officers, 4.41 per cent in the case of Class II, and 10 per cent in the case of Class J II. Then we come io the Public Undertakings. I have calculated the percentages. In the Public Undertakings, the representation is less than one per cent in class I, it is also less than one per cent in the case of Class II, and less than 7 per cent in Class III. This is the performance of Public Undertakings. As regards the Railways, their representation is 3.8 per cent in Class I, 3 per cent in Class II, and 8 per cent in Class III. If these Public Undertakings and the Railways, who are under the Government itself, do not consistently implement the Government's policies and the constitutional directives, what else can we expect from Private Undertakings ? I think, first and foremost, the Government must have a determined will to implement the recommendations of the Report in toto. In another year, there will be another report, and we are getting every year proto type copies. What is needed is implementation. 'Implementation today' should be the slogan for the Government. They should implement the recommendations of the Commissioner.

[Mr. Deputy Chairman In the Chair]

Sir, lastly I Come to the special training facilities. Why should the Harijans alone do the scavenging work ? Why should it not be done by other people ? Similarly, why not the Harijans be given proper training so that they can go to other professions, other than scavenging and dirty and unclear works ?

[Shri B. T. Kamparaj.]

Sir, there should be some time limit or target for implementation of the programmes. One should be longterm and the other short-term. Each State can have its own target and short-term programme achieve it in a year. Each block and district can have their targets and get them implemented. I want that there should be a special machinery from Centre to the village level. That machinery should be organised in such a way that there must be Teports from the village to the Centre so that these can be implemented by this machinery. They should organise their activities in such a way that they come into contract with Harijans people and know their experiences. Accordingly, these programmes will be implemented in each village with village people.

Sir, what do we see in India today 1 Only five States have got 50 per cent of this sub-human population. Out of 13 crores, you will find more than 7 crores in five States, the people who are called untouchables. In Uttar Pradesh there are ready 2 crores, in Madhya Pradesh nearly ! 150 lakhs, i.e.. 1.5 crores, in Bihar 1.28 crores, in West Bengal 1.13 crores, in Orissa 83 lakhs and in Tamil Nadu 76 lakhs. So. we have five States in India where a majority of this sub-human community is living. Government should have the practical sense of improving the conditions of these classes. Our efforts should be centralised in those areas where their population is thickly congested. About a year back in the Rajya Sabha it was reported by the hon. Minister Mirdha-saheb that more than 1100 cases of murder happened during 1967 to 1969.

Sir, there are many cases. I shall state some case. The Report says that there have been 1800 landless people. Out of these 1800 landless families have been given land, of whom the number of Scheduled Castes was only 338. About 73 per cent Harijans work on land. All of them are very poor. All these people are not getting sufficient land for their home-sites as well as for their cultivation. Whichever land is given by Government allotment, it is grabbed by the vested class of the local village people. These vested interests want to see that these poor people have no other means of livelihood than bonded labour. This ts how the things go on.

Some other cases are also there. I shall not quote many because time is short. There are many cases under the Criminal Procedure Code but only a few of them go to the court. Out of lakhs and thousands of cases only a few cases go to the courts. Even when these few cases are taken to the courts, the vested interests threaten these people and enter into some compromise agreements which favour them
and not these downtrodden people.

I say land is not reaching these people. Justice is also not reaching these people. Economic benefits are not reaching these people. They do not know what are their constitutional benefits and what are the benefits provided to them under the Directive Principles. Machinery of publicity should be wide enough to reach the people at large. The Ali India Radio should have a programme feature for enlightening and educating these people in the villages. In every village you have some transistor radio. So, these people can listen to these things. I would request Government that every month or even every week they can have some talk broadcast over the AU India Radio for these people, so that they can have some inspiration so that they can organise themselves and so that they can assert their own rights for the future which future they are ordained to build for themselves and other peoples in peace and amity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will sit today till 5.30 p.m. because there are a large number of speakers.

SHRl N. JOSEPH (Andhra Pradesh!: Sir, the Commission has submitted its

Report on Scheduled Castes and Scheduled Tribes 1970-71 and we are discussing this Report in this House. Our Constitution has sanctioned special privileges for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. They have been in force for the last 23 years. Our Government, our leaders and ali the people have been doing I heir best to see that these Scheduled Castes and Scheduled Tribes are brought in line with the other forward communities in the countiy. Not only the Constitution has sanctioned some of these special privileges but the leaders of the country have been frequently advising the people to put these special privileges in practice. Our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi has been often warning and appealing to the people to hsip these Scheduled Castes nnd Scheduled Tribes and bring them on a par with the other communities. In spite of all these, in spite of the special privileges, in spite of the laws and other things no satisfactory progress has been made in implementing these. Where does the mistake lie? We find that the mistake lies in the implementation only. Why implementation is nol done strictly is because the country is addicted to ihe caste system, because the bureaucracy and the machinery which is in power—which is the main organ to put all these things into practice is imbibed with the caste system, imbibed with ill feelings of caste, this implementation could not prove a success. Therefore, unless and until stringent measures are taken against the bureaucracy or the machinery if it fails to see that all the laws and special privileges are put into force strictly, nothing can help these Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is my conviction and that is the main point to consider about Scheduled Castes and Schednled Tribes.

Sir, we have been discussing about the defects in implementation. What are the reasons ? Why are the people not co-operating? Because we did not get our independence by revolution. We got our independence by evolution, by a new method of Satyagraha and non-violence. So we could not remove those bureaucrats who prosecuted our leaders and satyagrahis, who killed them, persecuted them and put them in jail, were kept intact in the Government machinery and those people are allowed to rule the country. The progeny of those people is continuing today also and we cannot expect much from them and, therefore, our implementation is an utter failure.

Sir. for all these things the casfe system is the main basis. The caste system has been running in India for centuries and caste system is associated with professions and ' the caste system has been given religious sanction in our country. Of course, we could not do much about it because of religious sanctions. However, in spile of holy sanctions by religion, our leaders have been fighting against the system. Even Mahatma Gandhi fought against these things. Though he was pure in religion and in spirit he fought against this system. In spite of that we could not go forward because the caste system is imbibed in the minds of the people and in the minds of the rulers of this countiy.

After independence, Sir, a new caste system has arisen and that is the caste election system. In each election, each party selects a candidate in such a constituency where a particular community is dominating. No party is an exception to this. And that candidate, unless he appeals on the basis of caste, will not succeed. In an indirect way the caste system has been increasing after independence. We have been seeing Harijans and others being harassed, not because of the caste system that is inherent in our people and our country but because of the new caste system for election purposes. Where those Harijans were voting against the rich candidates and the rich parties, those people were being harassed, being killed. And even today that is what we see during elections anywhere in the country.

[Shri N. Joseph.]

We have been appealing to the people of the basis of the caste system. The Government is there to take action against people who are going to corrupt people by money, hut where is prohibition of candidates appealing on the basis of the caste sysiem ? Nothing has been done, no rule is there. Unless these things are done away wilh in Ihe country, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be brought into line with other people. I am afraid. Sir. there is a lot of things to do to bring up the Scheduled Castes. Merely helping them in education, merely giving them scholarship, merely giving them jobs would not do; unless and until we implement the land ceilings and urban ceilings and distribute the excess land to agricultural labour, to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes no Government can succeed in bringing them up to the level of other people. Untouchability cannot be removed unless they are economically brought up to the level of others. You should not only uplift them economically but also remove the social stigma. And if you want to remove this social stigma and other things the leaders of all the parties should together find a solution and they should take up an aggressive propaganda among the people to do away with the caste system and untouchability. No law can help to remove untouchability, this social stigma, poverty and all these things. I would therefore appeal to the leaders of all the parties to come together and find out a solution but not to blame the party in power alone. It is no use blaming them. It is not only the Congress Party or the ruling party that can do these things. The leaders of all the parties in the country together should fight against this evil, this permanent evil of the country. Then only there can be salvation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, our country is committed to secularism and socialism. Not only our country is committed but the leaders of our country are all committed and they have been trying their best to see that these ideas are pat into practice*. What is secularism? Secularism means no individual can be discriminated in any way merely because of his religion. That is secularism. But unfortunately in our country a section of one caste is eliminated and denied alt privileges because they accepted a different religion. Because a section of the Harijan community accepted the Christian religion they are being denied all the special privileges available to their Harijan brethren. They live along with the Scheduled Castes in the same cheri, they are being buried in the same graveyard when they die, they are undergoing the same poverty, the same ignorance, the same illiteracy but in spite of all this these people are denied all privileges simply because they accepted Christianity. Is that justified in a country like India to discriminate against such people? Our country, India, is famous for its spirit of toleration; in the whole world there is no other country where there is so much of toleration and in such a country this is the discrimination practised against a section cf the people. Why should it be so ? Why this religious fanatacism ? AU through his life the Mahatma fought against such religious fanatacism and it is known to the whole world. Why should some people say that Chistianilv is not a religion of Bharat? Is not Christianity a Bharat religion? Long before others Christians were existing in Kerala from first century A.D. If that is so, how can that not be a Bharat religion? Before Aryans came to India the present religions were not there. Just as Hindu religion came to be established Christianity also has been here since a long time; so let us not be bothered about it. These are all purely spiritual questions which have nothing to do with politics. Let us not bring them into the political arena. If it is brought into the political arena we will only be doing harm to our own country. One section of the community should not be eliminated on the basis of religion. Therefore, I appeal to our Home Minister, Mr. Dikshit, and Mr. Mirdha and I

request Mr. Mirdha to carry it to Mr. Dikshit, to appoint a committee to find out whether the Scheduled Caste Chris tians are undergoing all Ihe disabilities just like their hrother-Harijans. whelher they are living in the same' 'Cherries' or not, whether they are suffering from the same kind of illiteracy, ignorance and poverty. All these things are there. Then, the com mittee can submit a report and say whelher these people can be added on Io the Sche duled Caste list or not. 1 appeal to them to appoint a committee to go into these things. Jn Andhra where there are 45 lakh Christians. 99 per cent of them are converts from the Harijan community. In Andhra 45 lakhs are converts from Hari jans whereas 90 lakhs still remain Hari jans. When a Harijan Christian goes for a job, the officer says: You are a Christian and you will not be given a job. When he goes in for a piece of land, he says: You are a Christian and you will not be given a land. When he goes in for a house-site, he is told that he will not be given because he is a Christian. When he goes in for the cons-truction of a house, he is told: You are a Christian and you will not be given a house. When he goes for a loan of Rs. 1,200 for purchasing a buffalo, the officer says: You are a Christian and you cannot get any loan. What is this? ls this justice? Is this flow our country should treat the poor people? I would tell the House that no religion can be killed because of such pressures. The Christian community withstood the sword for three hundred years after Christ. There was persecution and there were killings. Whoever said that he was a Christian was persecuted. He was thrown to the wolves and to the lions to be killed for three hundred years continuously. Ir. such a great turmoil the Christian community survived. So, when the Christian community could withstand the same, how can anybody think that he can destroy this religion? We can withstand the sword and be killed in a moment, but we cannot suffer this always saying: If you want to get this job, you must convert yourself into a Hindu. Let not our country get a bad name by doing this. You may argue that there are Christian missions and Christian agencies who are helping these Christians. There is an international organisation by the name of CASA which has been supplying crores of rupees worth articles. They have been supplying wheat flour. Crores of rupees are being spent on that. It is a Christian organisation only in name and it does not practise any discrimination. They do not give anything based on caste or creed. Unless we say that there are all people from all sections, they are not going to give us aid. Though it comes from a Christian organisation, they do not say that Christians alone should enjoy it. So, why should we say because he is a Christian, he will not get a job? Why should he not enjoy the special privilege that is being granted to his own brother-Harijans? So, this thing is not justified in our country. I appeal to the leaders lion. Members of the House and also the Home Minister to take care of this thing. Appoint a committee to find out whether the facts I say are true or not. We have two colleges in Guntur, where I was the President of the District Congress Committee for five years. In that college more than 55 per cent lecturers were non-Christians and more than 70 per cent of the students were non-Christians. There arc three or four hospitals in Guntur. More than 70 per cent facilities are given to non-Cbristian people. No special privilege is shown to the Christian people. Such is the case in the Christian institutions of the country. Such being the case in our Christian institutions, why is it that our country is showing discrimination between the same caste? Special privileges are allowed to some people. On what basis it has been allowed ? It is not because of being a Christian or a non-Christian. It is because of the caste system. It is because of the social, economical, cultural and political backwardness and down-trodden conditions of these people. For these reasons these people are given special privileges. When the people are victims of the same kind of disabilities, why should the other section be deprived of special privileges as

[Shri N. Joseph.]

are being given to the Harijans? I appeal to the House and the leaders. There should be economic and social upliftment.

(Time bell rings)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You will have to wind up now.

SHRI N. JOSEPH : Until and unless economic, social and political upliftment is given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is no use granting them scholarships and appointments. The Government should immediately take steps to put land ceiling, urban ceiling in force and distribute the land among the common man. Educated ycung men are suffering. Educated Scheduled Caste men too will be suffering. Unemployment is rampant in the country. Who can solve this problem ? Therefore there should be ceiling over and above a particular income. A person owning property worth above a certain value ."hould not be given job in the country. A person who does not own land should be given preference in jobs. Unless you bring such a legislation nobody can solve the problem of unemployment in the country. Industries must be started in abundance. Land ceiling must be put in force. All these things should be taken into consideration. I, therefore, appeal to the Vfinister to appoint a committee to find out the difference between the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Scheduled Caste Christians and to remove that disparity. And add Scheduled Castes Christians to the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. An appeal should be sent to the President to remove any bar against the Scheduled Castes Christians and Scheduled Tribes all over the country. With these words I take my seat.

SHRI G. A. APPAN fTamil Nadu) : Mr. Deputy Chairman, Sir, f have repeatedly said that rather than doing anything very, very late after the egg is addled it should be our endeavour to see that wrong things are either ended or mended sooner than later. Let us be icalistic in our approach. Many people say that so many safeguards are there for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Sir, 1 should be naked and frank in mv utterance today...

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : You should be frank but not naked.

SHRI G. A. APPAN : I will be naked in my remarks. All the so-called provisions and protection for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes are a farce. I will just tell a small story before coming to my speech proper. There was a Pastor of a church. On a Sunday he was preaching not to steal. Every Sunday his wife used to remain outside and according to the instruction of the Pastor tried to catch hold of a very nice fowl from the neighbour's house and cook it for him. One day he was preaching not to steal others' property. When he went back that particular day to his house for lunch there was no fowl for his dish. He got wild with his wife. He said I purposely went on preaching about this for a long time so that you could get the best fowl fiom the neighbour's house. But the wife said "You said that we should not steal". He said, '"It is for others and not for you". So this is what is going on in our Government now. The so-called protection, safeguards and things like that are given in the Constitution are not written on the hearts of officers and Ministers but they are written on a white paper.

Perhaps a trash of white paper is the Constitution. Mrs. Gandhi says "garibi hatao". And every Member of her Cabinet says "garibi hatao". Most of her Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers say that the principles vouchsafed in the Constitution should be kept up, should be implemented. But what happens? In the Central Cabinet rank here out of 17 Ministers, poor Mr. Jagjivan Ram is the only one from the Scheduled Castes. How many should we have? Is it not four, my dear friends?

Ana now can we taice ner word tor granted? I have said this every year, not once but twice, thrice . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Appan, you are factualy a little wrong. Mr. Bhola Paswan Shastri is also there.

SHRl G. A. APPAN: Pardon me, Sir.

DR. K. MATHEW KURIAN: It is a hundred per cent increase.

SHRI G. A. APPAN: Anyhow, Sir, is there one member of the Scheduled Castes in the rank of Minister of State? All right though this be the position at the Cabinet Ievel in the Centre. But excepting in Tamil Nadu, I do not know how many States have given one-fourth of the total number of Ministers to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Leave out ihe Ministers. You know, the President is there, the Vice-President is there, the Prime Minister is there, the Speaker is there, the Deputy Speaker is there, the Deputy Chairman is there and the Vice-Chairman in both the House is also there. Should we not have at least one or two fellows from our community in these ranks? Why not? You know, the late revered Mahatma Gandhi used to say, "How can I be happy unless I see a Scheduled Caste man adorning the Presidential %addi?" I would not say Presidential gaddi, which is imam ke waaste; 1 would say that the Prime Minister of India should sooner or later be a Scheduled Caste-man.

DR. K. MATHEW KURIAN: You want Mrs. Gandhi to resign?

SHRI G. A. APPAN: All iight, let her be there. As long as she is there, she says. "Let us try to implement it", but many people do not even say it. We have repeatedly said that Mrs. Gandhi is not a had person. As matters stand now, we have no better alternative—that is, in the words of our Chief Minister.

DR. K. MATHEW KURIAN: Mr. Jagjivan Ram.

SHRI G. A. APPAN: Also we do not want all these people. One cannot always be there. We have got young blood. I request Mrs. Gandhi to see that the spirit of the Constitution is implemented in the Cabinet and she should also give instructions to all the State Governments run by her party to have the Chief Minister there from among the Scheduled Castes, and at least one third of the Ministers should be from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Mr. Deputy Chairman, on pages 38 and 39 of the Report for the year 1970-71, we got statistics to prove how honest they are. On 1-1-1956 in Class I, ICS/IAS service, the percentage of Scheduled Castes was 0.17 per cent. No doubt in 1971, it has risen to 6.82 per cent. But what is the percentage that is promised? Is it not 17-1/2? Do you mean to say that we do not have graduates or doctorates among us. Do you mean to say that we not have MA degree holders? When the great Dr. Ambedkar could draft the Constitution in a record time in the whole world, when Mr. Jagjivan Ram could run Ministries like the Defence and Agriculture very diffi cult portfolios, very efficiently, how do you think that we do not have people who are not competent for any type of work? Then, in the later portion of page 38 of the S.C.C. Report—1970/71, the percentage of Scheduled Castes in IAS and 1FS in 1961 was 1.9, Scheduled Tribes 4.1. In 1970 the percentage of Scheduled Castes in IFS was only 6 and that of the Schednled Tribes only 0.4. In the Central Secretariat Services the Scheduled Castes in Class I constituted only 2.3 per cent, Scheduled Tribes only 3.3 per cent, and in Class II 5.9 per cent, Assistants-—non-Gazetted— 5.61 per cent. In the Central Secretariat Stenographers' Service it was only 1.9 per cent as private secretaries to Ministers. And in Stenographers Grade III only 5 per cent is there. Tn the Central Secretariat I Clerical Service the position is even worse. In the Railways you will be shocked to

|>hn (J. A. Appan.j

see that in Class I the Scheduled Castes percentage is only 3.88 and in Class II only 3.25 and in Class III only 8.68 and so on. Even for clerks' jobs—a job which requires only SSLC or Intermediate or PUC—officers say that we do not have sufficient numbers. In the IPS, IAS and IFS we are reaching our quota in all ths recent years. But for LDCs, UDCs and Stenographers, vested interests say that we are not having a sufficient number of candidates. That is only betraying lack of one's own sincerity and honesty in one's desire to carry out the spirit of the Constitution. In the State and Central Services reservations are provided. But in local boards and local bodies there is no resei-vation provided under the Constitution. Seldom do we get even I per cent or 2 per cent representation in the local board services. In the House of the people and in the Legislative Councils in the States we are not getting even 1 per cent or 2 per cent representation. Under these circumstances, may I ask my revered friend, Mr. Ram Niwas Mirdha, to bring home to the Prime Minister that the true and urgent need of the day is that the Constitution should be so amended to make provision for reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, not so much more, but at least according to the percentage of their population in each State for the State Legislative Council and in the (Rajya Sabha) Council of States. We have a number of statutory bodies, councils; Boards and similar institutions in the Central sector as well as in the Stale sector. Will it not be possible for the Government of India to see that they pass an enactment saying that wherever we have a Constitutional institution, a statutory institution, getting recognition or aid loan and support from the Government should make it a point to appoint or provide 25 per cent reservation for the Scheduled Castes and 10 per cent reservation for the Scheduled Tri bes°

Fortunately in Tamil Nadu the Chief Minister is giving the maximum encouragement to the Scheduled pastes ap-\ Tribes m the matter of housing through the Slum Clearance Board. He is also giving a number of Chairmanship of statutory bodies like the Small Savings Scheme . . .

SHRI N. P. CHAUDHARI (Madhya Pradesh): How many of them are in the Cabinet in Tamil Nadu?

SHRI G. A. APPAN: Out of 14, we have 2 people.

In foreign service we are not given any representation. We are not adequately represented in the matter of appointment to the posts of Vice-Chancellors of Universities. We have only two Governors out of so many in the country. When we visited Himachal Pradesh, we heard that the Scheduled Castes people there were not getting scholarship in time and that they are also not getting scholarships according to Constitutional provisions. Government should ensure that full employment is given to Scheduled Castes and Tribes once they fulfil the educational qualifications.

Coming to inter-caste marriages, these should be encouraged everywhere according to the Constitution. But how many of the States are sincere in this matter? It is a great history that the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. K. Karunanidhi has set a good example for the whole country in this matter. He has married his own son to a member of the Scheduled Caste community. Will all the Chief Ministers and other Ministers take a lesson from this and have inter-caste marriages performed in their own homes? Even Gandhiji who spoke of inter-caste marriage married his own son to the daughter of a Brahmin -late Shri Rajagopalachari. But let us not speak like that. Let every Minister, let every Governor, other senior officers, big and rich men. industrialists and businessmen take a lesson from the example set by the Chief Minister of Tamil Nadu and encourage inter-caste marriages amone their own sons and daughters. Sir, we are giving medals to many people for doing wonderful things like inter-caste marriages.

Central Government should consider it as a prerogative to make such an award for our Chief Minister. Of course, our Chief Minister does not very much mind about i these things. But what he did should be recognised all the world over. Let Mrs. • Gandhi and Mr. Giri take this lesson to j their colleagues and all the Ministers.

In the temple there are trusts. In Tamil Nadu we have introduced a system that even where there are only two members in a temple trust, one of them should be a Scheduled Caste person. In other words, there should be no temple trust unless one member among the members is a Scheduled Castes man. Will the whole country take a lesson from this example ? Will the Prime Minister and Home Minister consider this '.' In Tamil Nadu, under the DMK Government, even priestship can be conferred upon Scheduled Castes. And, Sir, I am told that it is no! allowed to implement the process of appointing the temple priests. That is why we sav that even in small matters the Central Government and the Supreme Court begin to interfere and that is why we say that we want State autonomy. Now, Sir, State autonomy is getting greater support in almost all the States. Even to appoint somebody in a small job we want the concurrence of the Central Government. The Supreme Court stands in the way. Sir, the first Scheduled Castes Judge has been appointed in Tamil Nadu. How many other States have appointed Judges from the Scheduled Caste. In the Supreme Court, Sir, not even a single Judge has been appointed from the Scheduled Caste. When are we going to have Chief Justices of the High Court and the Supreme Court from the Scheduled Caste people ? Muslims, Brahmins and others have become Judges and Chief Justices—too but not a Schedule Caste man. Will the honourable Minister please bring this fact to the notice of the Prime Minister ? T hope, Sir, today, on her birth-day, Shrimati Indira Gandhi would wake up and make some noval arrangement, she may try to start some trust or some such thine.

or the Scheduled Caste people and also or the abolition of untouchability by sneouraging inter-caste marriages. Then, Sir, I will request the honourable Minister 0 do one more thing. In the city of Delhi, housing facilities for the Scheduled "aste people are very very poor. Will the Central Government take it upon itself to see that the Harijans are provided with ;ood housing facilities, drinking water faci lties, and compulsory employment and >o on throughout this country? Will the Government also see to it that they are also provided with compulsory education at least up to the 8th Standard? And, also, Sir . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to conclude now.

SHRI G. A. APPAN: I beg your pardon. Sir. 1 want two minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I will allow you only one minute more. I have allowed you enough.

SHRI G. A. APPAN: No, Sir. I want two minutes more.

Sir, I have been requested the Civil Aviation Minister to provide jobs to the Scheduled Caste people in the Air Corpo rations and also the Finance Minister to provide jobs in the banks. These two Ministries have constituted a number of committees and Boards. But not a single fellow from the Scheduled Castes has be come a member of these bodies. Not only that. Regarding appointments also, in the Air Corporations and in the banks many appointments are made. But they are not for the Scheduled Caste people. Similar. Sir, is the case in respect of loans granted by nationalised banks also. Therefore, I want a powerful parliamentary committee to see that in every sector, smaller or big, the representation allowed for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is proper-j ly maintained. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr 1Kalyan Chand.

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, बड़ी खुशी की बात कि हम शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं । अनेक विरोधी दल के सदस्यों के भाषण मैंने सुने हैं । उनकी सरकारों के कार्यकलाप भी देखे हैं, उनके प्रचार का ढंग भी हमने देखा है, उनमें हरिजनों के प्रति कितना प्यार है उनको भी हमने देखा है । सदन में आकर के वे भाषण देते हैं कि हरिजनों के उत्थान के लिये कुछ नहीं हुआ । एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि हरिजन विधान को क्या समझें। हरिजन ने तो विधान को बनाया है। विधान आप की समझ में नहीं आता है। हरिजनों को विधान खूब समझ में आता है। इस देश में हरिजनों ने विधान का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन भी किया है। माननीय विरोधी दल के नेता बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि 26 वर्षों में अछूतों और हरिजनों के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरा खयाल है कि बहुत से माननीय सदस्य पहले कांग्रेस में थे और उनके ही नेता मुख्य मंत्री थे। उनके समय में जो कुछ हुआ और हरिजनों के उत्थान के लिय जो उस समय कोई विशेष कार्य नहीं हो सका, उसके लिए वे क्या सजा भुगतने को तैयार हैं ? यहां बैठ कर उनके लिए केवल आंसू बहा देने से कोई लाभ नहीं है । माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से उन्होंने हरिजन डिपार्टमेंट संभाला है, तब से हरिजनों की भलाई के लिए बहुत काम हुआ है।

5 P.M.

माननीय मंत्री जी ने अभी पिछले जमाने में जो हरिजनों को जो 15 परसेंट प्रमोशन में और साढ़े 7 परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोशन में चांस दिया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । इससे हरिजनों का उत्साह बढ़ा है। यह बात सच है कि जहां मंत्री जी ने इस प्रकार उनको प्रमोशन में ज्यादा सहूलियतें दे कर उनका उत्साह बढ़ाया है उसके लिए अधिकारियों को भी सचेत रहना चाहिये था, लेकिन वे इस मामले में उदासीन हैं । अधिकारियों के कदम उस तरफ नहीं उठे और यही वजह है कि आज हरिजनों में असंतोष है । सरकार ने उनके लिये जो-जो कार्य किये हैं उन को छिपाया नहीं जा सकता । अभी हमारे तमिल नाडु के एक मित्र सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या मन्दिरों में हरिजनों को जाने दिया गया । म कहना चाहता हू कि आप पूरे भारत की बात न करें। आप जहां हैं वहीं तक सीमित रहें। तमिल नाडु सरकार ने भले ही उनके लिए कोई नया काम न किया हो, जिस के लिए वह उछल रहे हैं, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि कन्हैया लाल सोनकर को हमारी त्रिपाठी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बदरीनाथ मंदिर में रिसीवर के पद पर नियुक्त किया है, आप को पता क्या है कि पिछले 25 वर्षों में हम लोगों ने उनका कितना उत्थान किया है । यह बात सच है कि आज भी छुआछूत का बोलबाला देहातों में है, लेकिन केवल सरकार ही तो उस को समाप्त नहीं कर सकती । छुआछूत को समाप्त करने का कार्य तो जितनी सामाजिक संस्थायें हैं, उन सब को मिल कर करना चाहिये । मैं जानता हूं कि विरोधी दलों के माननीय सदस्यों की कांस्टीट्युएंसीज में ही ज्यादा तर उन पर ही जोर जुल्म हुआ है। क्या उस का पता उनको नहीं है ? जब उत्तर प्रदेश और अन्य 9 प्रदेशों में सम्मिलित दलों की सरकार बनी थी, उसी समय से हरिजनों ने आपको खूब अच्छी तरह से समझ लिया है। हरिजनों का विश्वास कांग्रेस से हट चला था और वह समझने लगे थे कि कांग्रेस उन के लिये कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उस के बाद जब 9 प्रांतों में सम्मिलित दलों की सरकार बनी तो उन्होंने देख लिया कि वे लोग उनके लिये क्या कुछ करते रहे हैं और क्या कांग्रेस ने उनके लिये किया था। हमारे साथी वर्मा जी यहां बैठे हैं । जब उत्तर प्रदेश में रविद की सरकार बनी थी तो वह दस महीने की सरकार थी और उस समय हरिजनों के सारे अनुदान काट दिये गये थे। आज उन्होंने चर्चा की है कि उन को 500 रुपया व्यवसायिक के लिये दिया जाता है। जबकि आप के जमाने में तो केवल ढाई सौ रुपया दिया जाता था ।

श्री मानसिंह वर्मा : महोदय, मुझे तो यह कहना है कि कांग्रेस इसी प्रकार के कार्यों से आज शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों में उस का विरोध हो रहा है। शर्म आनी चाहिये आप लोगों को । यह अपने को कांग्रेसी कहते हैं ।

interruptions I challenge—(*Interruptions*)

श्री कल्याण चन्द : यह जनसंघ के मिनिस्टर थे । उनको शायद याद होगा और जिस समय शिक्षा विभाग

उनके हाथ में था, समाज कल्याण और हरिजन विभाग उनके हाथ में था, उस समय एक भी हरिजन टीचर को शिक्षा विभाग में नियुक्त नहीं किया गया और ज्यादा से ज्यादा हरिजन टीचरों को नौकरी से हटाया गया है, जब कि कांग्रेस सरकार में सारे दलों के लोगों को उन्होंने लिया था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज इतने जोर से वह चिल्ला रहे हैं। संविद की जिस समय सरकार थी, उस समय चरण सिंह जी ने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई नारा नहीं लगाया। क्या उन्होंने अपनी केबिनेट में किसी मेहतर को स्थान दिया ? हरिजनों में भी यह सब से निम्न है, क्या आप ने उसको कभी देखा ?

श्री मान सिंह वर्मा : क्या कमला पति त्रिपाठी के जमाने में शैड्यूल्ड कास्ट की लड़की को रेप नहीं किया गया ? अगर वह कोई बात कहेंगे तो जवाब भी लगड़ा दिया जायेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You made certain charges when you were speaking. Let him speak. He has a right to speak...

SHRI MAN SINGH VARMA : I have also the privilege to answer...

(*Interruptions*)

श्री कल्याण चन्द : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि चरण सिंह जी की जो सरकार थी जिसमें आप भी थे। उस समय शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आप ने नारा लगाया। लेकिन हरिजनों में जो सब से ज्यादा गरीब है और जो हरिजनों में भी हरिजन हैं उस मेहतर की तरफ भी क्या आप ने देखा ? आज श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर उत्तर प्रदेश में हमारे एच० एन० बहुगुणा की सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी मंत्री परिषद् में एक मेहतर को पहली दफा स्थान दिया है। क्या मैं अपने तमिल नाडु के दोस्त से पूछ सकता हूं कि उन्होंने तमिल नाडु में क्या उन को रिप्रेजेंटेशन दिया जो कि सबसे निम्न है, जिस का समाज में सबसे ज्यादा निरादर होता है ? क्या तमिल नाडु सरकार ने उनकी तरफ कोई तवज्जेह दी है ?

यह कहने से बात चलने वाली नहीं है। आपको मिल कर काम करना होगा। जिस समय आपकी नौ प्रांतों में सरकार थी, उसी समय से आप पर से हरिजनों का विश्वास उठ गया था। आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट भंग करने के बाद इलेक्शन आए तो एक भी हरिजन ने आपकी तरफ शक्ल उठाना पसन्द नहीं किया, एक-एक हरिजन ने कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने यह सोचा कि कांग्रेस की ही सरकार ऐसी है जो हमारी चिन्ता कर सकती है। हमने सब की सरकार देखी है, आपकी सरकार भी देखी है। आप देखें 24 वर्ष के अन्दर हम कहां गए हैं। आप यहां पर देखते हैं कि आज पार्लियामेंट के लिये टिकट कौन देता है (खास कर हरिजनों में मेहतरों को) आपने किसी को टिकट नहीं दी। तमिल नाडु से आपने किसी हरिजन को राज्य सभा के लिये टिकट नहीं दी, न आप किसी खटीक को यहां लाए, किसी धोबी को आप नहीं लाए। यह सारी नजर कांग्रेस वालों की ही होती है। यह सब आप को बुरा लगता है। क्योंकि हरिजनों के बारे में चिन्ता कांग्रेस ही करती है। इसी लिए हरिजनों का विश्वास कांग्रेस पर है। आपको जो बुरा लगता है वह हरिजनों को अच्छा लगता है।

लम्बी-चौड़ी बातें न कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर जुल्मोसितम होता है इसकी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि यह सामाजिक प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने उनके लिये क्यों नहीं नारा लगाया। आपने उन पर दया क्यों नहीं की। आपने छोटी-छोटी बातों पर नजर क्यों नहीं डाली। अब आप जोर-जोर से बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपने कुओं का अनुदान क्यों काटा, आपने इंडस्ट्री की ग्रांट क्यों काटी ? आपने हरिजनों के लिये छात्रवृत्ति क्यों नहीं बढ़ाई ? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंत्री जी को कि उन्होंने हमारी मांग को माना कि 50 परसेंट हरिजनों की छात्रवृत्ति बढ़ेगी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार का हरिजनों के प्रति मोह है। आप तो केवल बात ही करना जानते हैं। हरिजन उन बातों को अच्छी तरह जानता है। आपने पिछली दफा कहा कि आपने कानून बनाया कि वह चार आने देकर

[श्री कल्याण चन्द]

जनसंघ का मैम्बर नहीं हो सकता। क्या आपने ऐसा कानून बनाया कि हरिजन पानी पीने के लिये कुएं पर जा सकता है? नहीं बनाया। आप देखें हमारे यहां इस प्रकार का कानून बना हुआ है। आप तो केवल नारे लगाते हैं। हमने आपको देख लिया दिल्ली में। जब मेहतरों ने हड़ताल की थी तब आपने सरकार पर इल्जाम लगाया था कि हड़ताल सरकार ने करवाई है। आपने ही सरकार को मजबूर किया था डी०आई०आर० लगाने के लिये। आप मेहतरों को गरीब हरिजन नहीं समझते। क्या आपने उनके मकानों की व्यवस्था की? मुझे बड़ा खेद है कि आपने एक भी सफाई कर्मचारी के लिये मकान की व्यवस्था नहीं की। सरकार को अपना साझेदार बना कर आपने यह सब कराया। मुझे खेद है और यह बड़े शर्म की बात हो सकती है कि महज जनसंघ ने जनता को खुश करने के लिये यह सब करवाया।

मान्यवर, आज की जो रिपोर्ट है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जहां पर आपने हरिजनों को 15 परसेंट, 7 परसेंट रिजर्वेशन दी है, उसका इम्पलीमेन्टेशन जल्दी होना चाहिये। उसका इम्पलीमेंटेशन न होने पर अछूतों के दिलों और दिमागों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी एक साहब ने तकरीर की। एक साहब थे जो कि संडे को प्रीच करते थे और रोज कहा करते थे कि पड़ौसी की चोरी न करो, लेकिन उनकी स्त्री उनको रोजाना चोरी करके मुर्गी खिलाया करती थी। एक दिन उसने चोरी करके मुर्गी नहीं खिलाया तो वह कहने लगे कि मैं यह तो मुहल्ले वालों के लिये कहता हूं, तुम्हारे लिये नहीं कहता। ठीक यही मिशाल उनके ऊपर लगती है। वह तमिल नाडु की बड़ी-बड़ी बात करते हैं और जनसंघ की भी बड़ी-बड़ी बात होती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई एक मेहतर को भी मेम्बर बनाया है, जो सब से नीचे गिरे हुये हैं उनको क्या विधान परिषद् में लिया है. क्या वहां वह कोई मेहतर को लाये हैं? तमिल नाडु की बड़ी तारीफ कर दी, कितनी बात कह रहे थे, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां वही छात्र-वृत्ति दी जा रही है जो कि सैंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है। क्या आपने वहां अपना पैसा लगा कर कुछ छात्रवृत्ति दी है? तो इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है।

SHRI G. A. APPAN : The U. P. Uo-vernment has done the last for the welfare of" Scheduled Castes. There is untouchability even in elementary schools. And in every State, they get scholarships. You cannot deny that. Without knowing, the facts, please do not utter anything on the Floor of the House.

SHRI G. A. APPAN : Unbss you are full;,

श्री कल्याण चन्द : कितने स्वीपर आपके यहां गवर्नमेंट में आये, मिनिस्ट्री में आये। क्या आप इसको कह सकते हैं। जो सब से छोटे है, सब से गिरे हुए है उनमें से कितनों को आपने लिया।

SHRl G. A. APPAN : You want communities and professions. It is notorious.

श्री कल्याण चन्द : अब आप कम्युनिटीज़ पर आ गये। आप कांग्रेस की बात करते थे।

aware of the facts, please do not expose your ignorance.

श्री कल्याण चन्द : तो, श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में और झांसी में मेहतरों के मुहल्ले में आबकारी की दुकान है जो सर्वथा गलत है तो यह जो आबकारी की दुकानें वहां हैं, उन्हें वहां से फौरन हटा लेना चाहिये। वहां पर सफाई कर्मचारी बहुत तादाद में रहते हैं। लखीमपुर खीरी में जहां की सफाई कर्मचारियों का मुहल्ला है, वहां से आबकारी की दुकान फौरन हटाई जानी चाहिये।

DR. K. MATHEW KURIAN : Why are you insisting on so many sweepers ? You want to sweep the corruption under the carpet...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now let him continue. He has to finish his speech.

श्री कल्याण चन्द : दरअस्ल में बात यह है कि बात तो करप्शन की करते हैं लेकिन इनको झाड़ कर, इनको झाड़ू लगा कर वह खत्म करना चाहते हैं और बात करप्शन की करते हैं। अगर आप ठीक हो जायें तो देश की हालत बहुत बदल सकती है। कहीं यह झाड़ू उठा कर दूसरी तरफ न चल जाये इसको आपको समझना है।

लो, मान्यवर, आई०ए०एस० और पी०सी०एस० में, मैं यह मानता हूं कि पूरा कोटा दिया जा रहा है, लेकिन, मान्यवर, जहां तक तीसरी और चौथी श्रेणियों के कोटे का प्रश्न है, वहां पर हमारा जो कोटा है वह पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें। जब से मिश्रा जी यहां आये हैं इसमें काफी जोरों से वह लगे हैं और उन्होंने हमेशा इस बात की चेष्टा की है कि जितनी भी संविधान अछूतों को दी जा सकती है वह दी जा य और मुझे आशा है कि आप कृपा कर के हरिजनों को आगे ही बढ़ाते जायेंगे।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पिछली रिपोर्ट के समय भी कहा था, दिल्ली में बाल्मीकि के साथ "चूड़ा" लिखा जाता है, (शैड्यूल्ड कास्ट सर्टीफिकेट में) मान्यवर, मैंने इसके बारे में कई लेटर भी लिखे हैं, कई रिजोल्यूशन भी दिये हैं और आप ने विश्वास भी दिलाया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जितनी भी जगह हैं सब जगहों में बाल्मीकि ही कहा जाता है (स्वीपर लोगों को) लेकिन यहां पर जब तक स्वीपर को "बाल्मीकि चूड़ा" नहीं कहा जाता, तब तक शैड्यूल्ड कास्ट का सर्टीफिकेट नहीं दिया जाता। यह बड़े ही खेद की बात है। मैं फोरन इस संबंध में सरकारी निर्देश देने के लिये प्रार्थना करूंगा, आपका सरकारी निर्देश हो वह "चूड़ा" शब्द हटा लेना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं।

SHRl K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir, every year, for the last three or four years, we have been discussing the Annual Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the meantime we celebrated the Centenary of Mahatma Gandhi and last year we celebrated the Silver Jubilee of our Independence. But have these events say meaning for the 120 million Scheduled Castes and Scheduled Tribes ? 1 would say thai with all the progress that has been achieved, the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes along with the rest of the poorer sections of the people in the country have only deteriorated. With the characteristic understatement but with sufficient clarity the Report brings out this fact. The Report says : "The fact, however, remains that thes* communities have not generally been able to derive benefits of the Socio Economic progress of the country to any appreciable extent with the result that the gap between the Scheduled and non-scheduled classes h was fairly wide at the time of securing political freedom has continued to become wider and wider during all theso years." This is the inescapable fact ol life and this is the central fact of the whole thing and the situation is that these people have not been able to improve their conditions. On the contrary, their conditions have deteriorated. There are enough materials to show that this is so. For example, in a paper on the Green Revolution so many things are said and this is one of those wonderful things for which our Governmeat and the landlords and such people take credit. But. whal has been the result of green revolution '/ You know, Sir, that the vast majority of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are agricultural labourers or poor peasants. What has the green revolution wrought on their fate ? In a paper on the Green Revolution and Agricultural Labour presented to a three day seminar on Rural Development for the Weaker Sections in Ahmedabad. Mr. Pranab Bardhan, Economics Professor of Indian Institute of Statistics, New Delhi said that between 1960-1961 and 1967-1968 the weighted average daily wage rate for casual male agricultural labour—this has got a bearing on the life of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—in Punjab, Haryana, Delhi and U.P. had gone up by nearly 89 per cent but the consumer price index generally had also risen by 93 per cent. This indicates a decline in the actual wage rate despite an increase in igricultural produce by more than 60 per cent. Again, i Sir, during the period between 1964 and

[Shri K. P. Subramania Menon.]

1968 the daily money wage rate for male agricultural labourers in Western U.P. grew at an annual rate of 4.8 per cent while consumer price index for agricultural labour rose at an annual rate of 4.7 per cent, indicating a constant real wage rate. This was the position up to 1968. But, since then prices have gone up like anything and their conditions have worsened.

Then, Sir, another result of the great green revolution is this. In the Dhulia district of Maharashtra—one of those areas where the green revolution has really made a big dent—what is happening in the Sahada taluka of Dhulia District is that the landlords have formed them selves into a body called Purushottam Sena, or something like that. Adivasis call them Purushottam Sena. The Presi dent of the local Cane Co-operative Society, Mr. P. K. Patil is the man who has organised this thing. It is an awe-inspiring scheme. What are the facts of the whole thing ? He is going to organise an : >rce and call it watchmen, the capital expenditure for which will be Rs. 4.22 lakhs with an annua! recurring expenditure of Rs. 19 lakhs for a cultivated area of 4.74 lakh acres. Letters have been printed and circulated to all sar-panchs, village officials and landlords giving the blue-print of the Sena. What are the essential details of the scheme ? There will be 1200 Gorkha watchmen at the rate of one watchman for 400 acres. Above them there are hundred havaldars armed with guns and mounted on horses, each for three or four villages and then a commander for 30 villages wmed and also mounted on a motorcycle and above all these there will be a major and he will also be armed but he will be mounted on a ieep. And there would be an office with six clerks to have the administrative arrangements, accounting and sjl these things. These are being organised. Do you know, Sir, why ? Because the gujar landlords who have migrated from Gujarat to this District of Dhulia have been able to throw out the Adivasi peasants from that area. In fact, their lands were grabbed forcibly by these landlords. Now the Adivasis, their younger generation who are educated, all are trying slowly to organise and claim their lands back. Therefore, this knight errant of the green revolution, the great man of the revolution is organising this sort of activity in order to beat down the poor Adivasis and generally to gun them down, threaten them and intimidate them. What is the sort of going on ? I am still to hear either from the Maharashtra Government or from the Central Government what they are going to do about the activities of this sena. In fact, the Central Government has a special responsibility because according to the Constitution, the President can intervene in matters relating to the Adivasis and, therefore, I do not know why the Central Government is keeping quiet on this.

DR. K. MATHEW KURIAN : Is Mr. Mirdha aware of it ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You are there to remind him all the time.

SHRl K. P. SUBRAMANIA MENON : Then, Sir, I will come to another point that most of these concessions or privileges or grants etc. supposed to be given io the Harijans and the Scheduled Tribes are not reaching them and in many cases they are not implemented. New, going through the details of the post-matriculate scholarships given by different States, 1 find that two big States, Bihar and Rajasthan have given absolutely nothing as post-matriculate scholarships according to the Report. Why ? After all, it is the funds provided by the Central Government and I do not know why the Central Government does not look into it but it is found that they have not given a pie as post-matriculate scholraships. Similarly. there are a number of things wliich arc said in the Report but now I come to another point.

That point relates to the social disabilities of Harijans and Adivasis. Now, here 1 quote from some of the papers, especially Maharashtra papers. Analysing the for the present situation of the Harijans, the Maratha, a Bombay daily observes that the grip of the dominant tastes over the economy and political tern has become so strong that "they are bold enough to carry on ruthless exploitation and to suppress any resistance." This is what that paper says. That paper continues : "The social ferment started by Jyotiba Phule, Agarkar and Maharshi Karve stopped after independence." This is the tragedy, Sir. When the bourgeois wanted to mobilise the people to fight the imperialists they gave certain concessions, they tried to have some social consciousness and they also thought it fit to see that the vast masses of people including Ihe Harijans and Adivasis are drawn into the political struggle against imperialism. But once you got independence, bourgeois did not have any more use of these people and, therefore, they were left behind and the oppression which the imperialists had done, now the bourgeois is continuing. This is what happened.

Again. Sir, Maharashtra Times says Social conditions have changed considerably during the last 25 yean but this change is in degree, not quality. The exploitation of the downtrodden still continues. The methods of exploitation have changed and the exploiting class is different but even after 25 years of independence, just see, exploitation and illtreatment and suppression continues. Now you can go on quoting ;hese sorts of innumerable instances of exploitation and oppression of ordinary people. The latest incident I will tell you which is most shameful. I was awe-struck when I read this thing. This happened on October 5 in a city named after Gandhiji, that is, Gandhi Nagar, the capital of Gujarat. See what happened. "17 caste Hindus, Gujarati Government employees, were arrested by the Gandhi Nagar police yesterday for alleged assault on Harijan colleague, his wife, and five others, including two children. The State Government has so far not taken any departmental action against them and the traders in the State capital....."—mind you, Sir —"....traders in the State capital observed a total hartal yesterday in protest against the arrest", in protest against the arrest of people who committed the atrocity against a Harijan family. Now this is the social consciousness which after independence we have built. Now who is responsible ? The whole education system, the whole Press, and everything is responsible for this sort of thing. It is a shameful thing that blatant discrimination is done against Harijan employees of the Government. And do you know why he was beaten np by these caste Hindu employees ? "Mr. Dhanubhai Sakhalia, a Harijan clerk in the Capitat Project office and his Brahmin wife were alleged to have been beaten up for goinq to witness with caste Hindus at the Garha dance programme in the Navratri festival". That is the point because he had married a Brahmin girl and because he had gone and attended Garba dance festival. So the whole point that I want to stress upon is that the situation is not iu.u as if a few incidents here and a few incidents there are happening; it is not ihat. The entire situation is gloomy and the social consciousness of our people !s still at a very low level and they are not in a position to see the injustices done to the country as a whole and not only to these people, because the injustice done to these sections of our people is an injustice to the whole country and the problem of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not the problem of these classes alone. It is the basic problem of democracy in the country and unless it is understood in that spirit, it cannot be tackled.

Sir, now I come to another point and that is regarding some of the educational concessions given to them. This is my personal experience. Now recently, last

[Shri K. P. Subramania Menon.]

year the Council of Technical Education decided tha the Harijans and Scheduled Castes also should get reservation in the Indian Institute of Technology admissions. What happened is, a boy from my place-his name is Shashi—was selected in the All-India test for mechanical engineering course for admission into the HT. Now, as you know, Sir, people from Kerala suffer from two difficulties. One is the language problem, and secondly, he being a Harijan boy, all the good intention of the Government was subverted in practice by the foolish attitude of the authorities who implement those decisions. I will point out. This boy was allotted to the Delhi HT. Now, as you know. Sir, he has to come all the way. A young man of 17 years who has no knowledge of Hindi, not even very good knowledge of English, has to come here to Delhi. Then he comes and joins here. Initially he has to spend about Rs. 600 from his pocket. Now this is another thing. The Government should have seen to it that when a boy is selected for HT, he should not be asked to pay in advance Rs. 600/-. Of course he will get it back but how can a poor Harijan spend Rs. 600/- from his pocket, get a ticket from Kerala to Delhi ? It means a hell of trouble. Of course, he was helped by some friends from my village, and he came here. Then he was admitted into the hostel. Now in Ihe first instance itself he was beater.. A frail young boy, dark, his first experience is, he comes to Delhi and he does not understand the language. What he sees is these north Indian fair tall hefty boys who talk in their own language which he does not understand. And the first reaction he gets is he becomes terrified. And on the top of it as he enters the hostel in the name of ragging the boy is beaten; not only beaten for one day but he was beaten for one whole week and he was asked to clean the clothes of other boys, he was asked to clean the barracks and all that. And when he compla'ned to the warden, the warden says, what can I do ? Who has beaten you ? How does he know tlie name '.' He does not know the names because he could not understand the language. Just imagine the psychological impact to a young boy small dark young boy from Kerala coming and meeting these hefty north Indian boys in Delhi and getting this treatment. The initial mistake was, why did this Committee or whoever allots them, should have sent him to Delhi ? Madras would have been much better for him. He would have been more at home but he was senl here and the result was he had to run away from here. He ran away. He said. I will not remain here. He came to mc and broke down before me; I could not see that sight. He was very terrified; he would not go to the hostel. The authorities in the hostel and in the HT were unable to do anything. This is how things happen. And they got letters from him saying that he was going on his own accord and all that. If anv parliament committee goes, they would be told, we had one or two boys who ran away. This sort of information will be given but the circumstances in which that happened, the whole approach that contributed to his running away, that sort of information will not be given at all.

SHRI G. A. APPAN : It happens everywhere.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : I really do not understand why he was allotted to Delhi; he should have been allotted to Madras and then this sort of thing would not have happened.

There is another instance which I want to bring to your notice because we have been fighting this case for a long time. This sort of thing has also been brought to the notice of the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Quite a number of caste Hindus give false certificates for getting appointments and promotions in Government service. This has been brought to the notice of the Government many times

but nothing is being done about it. Here is a case the facts of which are these.

One Shri R. Rajagopalan, the present Sub-Divisional Officer, Telephones, Tri-chur, in the P&T Department has acquired his present position in tlie Department bv showing himself as a Scheduled Caste candidate both for recruitment and also for promotion in the reserved vacancies. The fact is he belongs to the Naidu community and by no stretch of imagination can the Naidu community be a Scheduled Caste. Mr. Rajagopalan is the son of Mr. Ramaswamy Naidu, retired Excise Inspector, trinjalakuda. Shri Rajagopa-lan's brothers are employed in the Electricity Department and the Reserve Bank of Indin. Shri R. Narayana Naidu. Junior engineer. Electricity Department, is now working at Cherpu Section, Trichur. Another brother, Shri Radhakrishna Naidu, is working as Agricultural Officer. Reserve Bank of India, at Madras. They all belong to the other backward community but never have they been classified as Scheduled Castes. In spite af repeated representations to the Government in the P&T Department, no action has been taken in the matter. The CBI also made an enquiry but I think under certain ' political pressures the Director-General of P&T seems to have set it asidj and a departmental enquiry was ordered. This fellow got some certificate from some Revenue Officer and has been doing this sort of thing. Such things should not be countenanced and I hope the Home Ministry will take serious note of this case and do what is necessary in this matter.

Lastly, before concluding, I want to point out that this question does not brook any more delay. The question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has become serious. Their oppression is so inhuman. There is also more awakening among them and that leads to clashes. Now, I would ask the Government whether their machinery will be on the side of the Scheduled (astes and Scheduled Tribes or on the side of the landlords and the upper castes in the name of law and order. Invariably it is always on the side of the upper castes and the landlords. When these people were oppressed, when illegal things were being done, when their girls were raped, then the law and order machinery did not work. The moment they rise in revolt as today they are doing it in Dhulia or some other places in U.P. the landlords resort to leonine violence, as it happened in Keelvenmani. The law and order machinery, the machinery of the State always goes to the rescue of the landlords, the owning class and the upper class. This is the tragedy of the situation. Unless this situation changes, 1 am sure under the resent set-up it is very difficult to change it. Even the courts are always on the side of landlords. Therefore, greater efforts are necessary, not only from the Government side, but also I would say every party in the country should take up this problem more seriously and work for the amelioration of their conditions. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 a.m. to-morrow.

The House then adjourned at thirty-six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 20th November, 1973.